(ग) और (घ) देश में कोकक्र कोयले की उत्पादन क्षमता को बढ़ाए जाने हेतु लगभग 9.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कुल क्षमता के साथ 14 परियोजनाओं को शुरू किया गया है। इसके अलावा, 4 कोकक्र कोयला ब्लाकों को "सेल" द्वारा ग्रहीत रूप में विकसित किए जाने हेतु बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है।

Export of Spices

*209. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the performance in regard to export of spices during the last three years;

(b) whether Government have planned to increase the export of spices;

(c) if so, the steps taken in that direction; and

(d) the specific steps taken to increase the production of spices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The export performance of spices during the last three years is given below:

Years	Value (Rs. Crores)
1992-93	418.64
1993-94	347.25
1994-95 (P)	607.31
1995-96 (Apr—Oct)	375.12
1994-95 (Apr—Oct)	301.92

(P) Provisional

(Source: DGCIS, Calcutta/Shipping Bills/Exporters Returns etc.)

(b) and (c) Yes, Sir. Government/ Spices Board has taken a number of steps for increasing export of spices. These include:—

(i) Quality evaluation and upgradation to international standards.

(ii) Promotion of expert of value added spices in the form of curry powder, spice oil and elecreasins branded consumer packed spices, dehydrated green pepper etc.

(iii) Strengthening the market base in existing markets and identifying new markets.

(iv) Providing assistance for promotion of specific brands by individual exporters in overseas markets;

(v) Popularising logo as a mark of Indianness and quality of spices in consumer packes;

(vi) Sponsoring sales-cum-study delegation, participation in selected international feed fairs and organising buyer-seller meets;

(vii) With the objectives of upgrading the quality, promoting export of value added spices from India and generating income and employment opportunities in spcies growing areas, a Project with UNDP assistance is under implementation, by the Spices Board.

(viii) Providing Grant-in-aid for setting up laboratory and accreditation of ISQ 9000.

(ix) Providing project feasibility report for establishment of curry powder/ground spices manufacturing unit.

(x) Providing assistance for setting up facilities for monitoring pesticides reside us.

(d) For increase of production of spices during 8th Plan, a centrally sponsored integrated programme for

development of spices with an outlay of Rs. 125 crores is being implemented. The major components of this programme are production and distribution of quality planting materials, area expansion, establishment of demonstration-cum-seed multiplication plots, distribution of mini kits and demonstration of plant protection measures.

Closure of FPS

*210. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of Fair Price Shop owners across the country have approached the Civil Supplies authorities for permission to close down their shops owing to poor profit margin; and

(b) if so, how Government propose to meet the situation?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

प्रति व्यक्ति चीनी की उपलब्धता में वृद्धि

*211. **श्री राघव जी:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी के उत्पादन में हुई वृद्धि को देखते हुए सार्वजनिक वितरण के लिए प्रति व्यक्ति चीनी की उपलब्धता में बढ़ोतरी की जाएगी; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) 1994-95 चीनी मौसम के दौरान बढ़े हुए चीनी उत्पादन को देखते हुए, सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए, 1 जनवरी, 1996 से 1991 जनगणना की जनसंख्या के आधार पर लेवी चीनी आवंटित करने का निर्णय लिया है, जबकि पूर्व में यह आवंटन 01.10.1986 तक की प्रक्षिप्त जनसंख्या के आधार पर किया जाता था। यह राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए चीनी की उपलब्धता की स्थिति को सुधारने में सक्षम बनायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मध्यावधिक मूल्यांकन

*212. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मध्यावधिक मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोई विशेष मध्य कालिक मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन में बताया गया है कि यह स्कीम आमतौर पर सभी क्षेत्रों तथा राज्यों में आबादी के कमजोर वर्गों के लिए लाभप्रद है। अध्ययन में स्कीम में कुछ कमियों तथा अवरोधों का भी उल्लेख किया गया है। उन्हें उपर्युक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाया गया है, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रोजाना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

(ग) और (घ) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लक्ष्यों का प्रस्ताव स्वयं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया गया था। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अतिरिक्त उचित दर की दुकानों, अतिरिक्त राशन कार्डों, जाली राशन कार्डों की समाप्ति तथा अतिरिक्त गोदाम क्षमता सृजित करने/भाड़े पर लेने के मामले में देश स्तर के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। केन्द्रीय सरकार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में हुई प्रगति